Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 20-12-2005
Participants : Chandrappan Shri C.K.,Singh Shri Arjun,Singh Shri Arjun,Yadav Shri Devendra Prasad,Gangwar Shri Santosh Kumar,Chatterjee Shri Somnath,Yadav Prof. Ram Gopal,Singh Shri Mohan,Radhakrishnan Shri Varkala

>

Title : Introduction of Constitution (104th Amendment) Bill to further amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: Let us take up item no. 28. Shri Arjun Singh to introduce a Bill.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Devendra Prasad Yadav, please take your seat. Wait for your turn. Why are you raising?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

Hon. Members, you are all aware that only legislative competence can be raised at this stage. Shri Devendra Prasad Yadav, I am calling you to speak. Please remember that rule and make your submission accordingly.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव महोदय, रूल 71(2) कार्यसंचालन नियमावली के तहत मैं आपकी अनुमति से अपनी बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 15(4) में स्पट है कि:

> "Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. "

इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम इस विधेयक के पूरे समर्थन में हैं। हमारा यह सब्मिशन है कि यह फर्स्ट संविधान संशोधन जो कि 1951 में पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के ज़माने में हुआ था, वह ऐतिहासिक संविधान संशोधन था। उसमें 15(4) में वर्णित सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आज यह बिल आया है। इसके नामांकन का जो मूल स्वरूप है, उसमें एक वर्ड socially, educationally backward classes of citizens जोड़ देने से मीनिंग स्पट हो जाता cè[MSOffice11]।

---

*Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 20.12.05

जब वर्ा 1992 में मंडल कमीशन आया, तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसे मैं आपकी अनुमति से यहां कोट करना चाहता हूं। वर्ा 1992 के बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड शब्द धुंधला नहीं रह गया है क्योंकि यह कांस्टीट्यूशनल वर्ड है। यह फंडामेंटल है और यह चेंज नहीं हो सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, मैं सिर्फ उस लाइन को यहां उद्धृत करना जरूरी समझता हूं। आर्टिकल 15(4) और 16(4) को किस तरह से डिफाइन किया गया है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गयी है, वह मैं बताना चाहता हूं।

> "Article 15(4) speaks about socially and educationally backward classes of citizen while article 16(4) speaks only of any backward class citizen. However, it is now settled that the expression 'backward class of citizen' in article 16(4) means the same thing as the expression 'any socially and educationally backward class of citizen in article 15(4). In order to qualify for being called a backward class citizen, he must be a member of a socially and educationally backward class. "

माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी, हम लोग इस पर सहमत हुए हैं, लेकिन जैसा संकेत किया गया है कि ऐम्स एंड आब्जेक्ट्स मेनडेटरी नहीं होगा, तो हमारा कहना है कि यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट है और आज के बाद ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जायेगा, क्योंकि जो मूल प्रारूप है, मूल ड्राफ्ट है, वही एक्ट बनेगा। हमारा

कहना है कि न मेनडेटरी हो और न ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स प्रभावी हो, उसके लिए ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में बैकवर्ड क्लासेज भी जोड दिया जाये। चूंकि अब ओबीसी प्रचलित शब्द है। यूपीसी हो या बिहार की कोई भी सर्विस कमीशन हो, वर्ा 1992 में मंडल कमीशन के आने के बाद जितने एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, यूनीवर्सिटीज हैं, जेएनयू, बीएचयू या आई.आई.टीज हैं, उनमें अभी तक मंडल कमीशन का लाभ ओबीसी को नहीं मिल पाया है क्योंकि कोई स्पट व्याख्या नहीं की गयी है।

MR. SPEAKER: That is a different point.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसकी स्पट व्याख्या की जाये। जहां एस.सी/ एसटी लिखा है, वहीं 'और' लगाकर ओबीसी शब्द जोड़ दिया जाये, यही मेरा सबमिशन है। मेरा यही निवेदन है क्योंकि एसओआर कहीं से मेनडेटरी नहीं है।

MR. SPEAKER: I am sure, your suggestion is well taken.

श्री संतोा गंगवार अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा भाई देवेन्द्र प्रसाद जी कह रहे थे, वह बिल्कुल ठीक है। यह बिल पिछले सप्ताह आना था परन्तु सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण बिल पर जो विचार किया गया, वास्तव में जो अमेंडमैंट किया गया है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। जैसा अभी कहा गया कि आर्टिकल के अंदर आप क्लासेज ऑफ सिटीजन शब्द जोड़ रहे हैं, तो उससे परपज हल नहीं हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि ओबीसी के हितों का इससे संरक्षण नहीं हो रहा है।

इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सबसे आखिरी लाइन जो इसमें जोड़ी जा रही है कि अधिकांश ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसे संस्थान हैं जहां उस जाति के लोग नहीं पढ़ते, बल्कि सामान्य जाति के लोग पढ़ते हैं, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे। मेरा आग्रह है कि स्टेट के एडेड और अनएडेड जितने भी इंस्टीट्यूशन्स हैं, वह सब पर लागू होना चाहिए। हम उनकी किसी व्यवस्था में, उनके संचालन पर हस्तक्षेप करने की बात नहीं कह रहे हैं, हमारा कहना है कि जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं, जिन्होंने देश के अंदर व्यवस्था में अपनी पहचान बनायी है, उसमें इस वर्ग के लोग स्थान पा सकें, पहचान पा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इस बात को इससे अलग करने का आग्रह किया जाये।

अभी जैसा देवेन्द्र प्रसाद जी ने कहा, यह वास्तव में सही है कि देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल नहीं रहा है। इस आर्टिकल के बाद उद्देश्यों और कारणों के माध्यम से हम ओबीसी की कैसे रक्षा कर पायेंगे ? न्यायालय के माध्यम से यह हमारे विपरीत जायेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो विपरीत बात हम लोगों के बारे में की जा रही है कि हम ओबीसी के समर्थक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग ओबीसी का पक्ष लेते हैं लेकिन उनका समर्थक बिल्कुल नहीं करते। वे उनके विरोध की बात करते हैं। उन्हें ओबीसी की बिल्कुल चिन्ता नहीं है।

MR. SPEAKER: Those hon. Members who have given due notice in time will be called. They have to hold their patience. I cannot call all of them together.

प्रो. राम गोपाल यादव श्रीमान्, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय संसद सदस्यों में कुछ कन्फ्यूजन cè[r12]। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, वह भी इसी संविधान के 15(4) के तहत लागू हुआ, लेकिन जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, वह बाद में प्रेसीडेंशियल ऑर्डर के जरिए कहा जाता है कि कितना प्रतिशत किसे मिलेगा। That process, Bill should also be applied after this process. क्योंकि पहले जो था, उसमें सर्विसेज में रिज र्वेशन का था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन जैसी चीज नहीं थी। This amendment is specially meant for reservation in educational institutions, whether aided or unaided. इसलिए कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। In the Objects and Reasons, it has been added. संसद के अंदर सरकार की तरफ से सरकारी विधेयक में ऑबजेक्ट्स में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स के आगे "दैट इज बैकवर्ड क्लासेज" अगर जोड़ा गया है तो इस पर भरोसा किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार राट्रपति महोदय के माध्यम से जो वारंट के जरिए एक आदेश जारी हुआ, राज्य सरकार एक अपना अलग से जी.ओ. करेगी, उनके तहत निश्चित रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन मिलेगा।

श्री मोहन सिंह अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही दिन इसका विरोध प्रकट किया था, लेकिन आज जो कारण और उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने परिचालित किये हैं, मेरी आशंकाओं का उससे समाधान हो जाता है क्योंकि जो मंडल कमीशन की संस्तुतियां भी लागू हुई थीं, वह भी राट्रपति महोदय की आज्ञा से हुई थीं। यह केवल प्रावधान किया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जा सकता है। जब शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान हो गये तो इस काम को राजाज्ञा के जरिये भारत सरकार शीध्रातिशीध्र करेगी, इस विश्वास के साथ मेरी आशंकाओं का समाधान हुआ। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN Sir, I do not straightaway oppose this Bill. But I am opposed to it on a Constitutional basis, to the provisions in the Constitution. As per the schedule of the Constitution, Education is a concurrent subject. So, the States as well as the Union Government will have powers to legislate on education. Here, in the instant case, the aim of the Government is to bring in a new sub-clause (5) – after sub-clause 4 - to Clause 15 of the Constitution. That is the aim of the Government. But it runs in conflict

with the provisions contained in the Schedule. Why? I may point out that in the Supreme Court judgement also, religious minorities include Christians, Muslims and all those religious minorities. To illustrate my point, I would submit that in the State of Kerala, 90 per cent or I may even put it, that 95 per cent of the un-aided educational institutions are run by these communities. Some of them are giving reservation in the matter of admission. When this amending Bill is passed, that admission will be stopped. So, the main question is that they are not duly giving any representation but still they are doing it.

MR. SPEAKER: That has nothing to do with the Constitution.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : But the question is: Which is the authority to decide, to identify a religious minority? It must be given to the State, not to the Centre. If you take the all-India average, Christians and Muslims will form the minority communities. But, when it comes to Kerala, it is otherwise. So, that is why I submit that there must be a provision to identify the religious minorities in the States. For example, in Mizoram, the Christians are in a majority and not in minority. But, on an all-India basis, it is entirely otherwise. So, when the question of religious minorities is taken into consideration, there will be difficulties. Therefore, the identification should be left to the States to decide.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Very well, first of all, let there be an amendment[R13].

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : With that provision if there is a definite provision with regard to identification of minorities, the Bill will become suffice.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are repeating.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Otherwise it will be in conflict with the interest of the States and hence, I oppose it on that basis.

MR. SPEAKER: Oppose the Bill!

… (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : महोदय, जम्मू-कश्मीर में भी यही स्थिति है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: There is no principle of association here.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I broadly support the proposal made by… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Very well. Nothing to do with constitutionally.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Actually, the point is that if this Amendment other than the minority education institutions referred to in Article 31, that part, if it is accepted, would take away the rights enjoyed by a large number of people in the unaided minority institutions … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: How? Under what line of reasoning, I do not understand. You can explain to him later on when you argue on the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN SINGH : Sir, as commonly understood, objection for the introduction of the Bill is raised on the legislative competence of the legislature.

MR. SPEAKER: You are right.

SHRI ARJUN SINGH: To the best of my knowledge, Sir, there can be no other forum competent to amend the Constitution than the Parliament itself.

MR. SPEAKER: I hope it does not have to be argued.

SHRI ARJUN SINGH: Well, Sir, sometimes the obvious is overlooked. I will not like to go into the other factors because there are issues which can be raised in the debate.

MR. SPEAKER: Yes, during the discussion.

SHRI ARJUN SINGH: I am sure in the discussions, all the hon. Members will give the best of their time and wisdom. We will try to see that the ultimate objective, as has been

mentioned very clearly, is to provide reservation for backward classes, SC/ST in educational institutions which, at the moment, does not exist. Therefore, I would like to request the Members to kindly bear with us. Let us discuss this Bill and then decide as to what needs to be done.

MR. SPEAKER: Have you been given some advance notices of arguments?

SHRI ARJUN SINGH: Yes, Sir.

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to move for leave to introduce a Bill futher to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I introduce the Bill.

MR. SPEAKER: Now, let us take up matters of urgent importance.

Shri Prabhunath Singh.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, in Tamil Nadu 42 persons died in stampede.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You know if you do that, I will adjourn and go there.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, the hon. HRD Minister is here. He should make a statement… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

I have not minimized importance of any of these issues. As a matter of fact, I have raised it myself from the Chair. I shall allow you, I have already assured you. Even then if you disturb each other, then nothing is being recorded. No one can raise any issue. There are important issues. Many Members have given notices but I am sure nobody will be able to suggest a method where two or three hon. Members can speak on two different subjects at the same time and that can be permitted.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please wait, I will allow you.

… (*Interruptions*)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, the hon. HRD Minister is here … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I know that. I have already said that. The day is not over.

… (*Interruptions*)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : The day is not over but he will go. Let him say he will.… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has to do it today.

… (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): I have been asking for… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has gone to the other House. He is coming.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, he is coming.

MR. SPEAKER: I have already instructed. Mr. Tripathy knows that very well. Please, you know that I have instructed. He is not here. There is another duty to perform[a14].

MR. SPEAKER: Let us utilise this time for raising important issues.

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Speaker, Sir, the HRD Minister who is dealing with the subject is present here. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do you have no faith in the Leader of the House?

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are an important Member. Please do not disturb the proceedings.

SHRI KHARABELA SWAIN : It is not a question of disturbing the proceedings. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

*(Interruptions) ...**

MR. SPEAKER: If you do like this, I will adjourn the House and go away. Then nobody will be able to raise any issue. The Leaders are here. Unless they can control all their Members, it will be very difficult to run the House. Can anybody get up at any time at his sweet will and disturb the House like this?

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Sir, the HRD Minister can respond. If he can reply now, it is all right.

---

*Not Recorded

MR. SPEAKER: Earlier you anted the Leader of the House to respond. Suddenly you are changing your stand.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY: He was absent at that time.

MR. SPEAKER: You know that I will adjourn the House. Then, nobody will be able to raise any matter here.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: The Chair cannot be dictated like this.

… (*Interruptions*)